an>

Title: Need to provide funds for irrigation projects in Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) ः जैसलमेर-बाड़मेर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 60,000 वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या 33 लाख है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का कुल 743 कि.मी. का क्षेत्र पश्चिम में भारत-पाक सीमा से सटा है। यहाँ आर्मी, एयरफोर्स एवं बी.एस.एफ. के सैनिक भी तैनात हैं। थार मरूस्थल होने के नाते यदि गत 60 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 40 साल का अकाल पड़ा है। इस साल भी 17 तहसीलों में से 10 तहसीलों में बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी है और यह क्षेत्र 85 प्रतिशत डार्क जोन है तथा शेष क्षेत्र में पानी जमीन में 400 से 1000 फीट नीचे है। साथ ही जो पानी है वह 2000-3000 टी.डी.एस. है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार पानी पीने योग्य ही नहीं है। इस पानी के पीने से लोगों को बीमारियाँ लग गई हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रयासों से 1995 में प्रारम्भ इन्दिरा गाँधी नहर जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुँची एवं नर्मदा नहर बाड़मेर पहुँची। इस पर आधारित बड़ी पेयजल योजनाएँ बनाई गई हैं। नर्मदा नहर परियोजनाओं को चालू करने में हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ा सहयोग मिला जिसके लिए मैं उन्हें क्षेत्रीय जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। दोनों नहरों पर 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार द्वारा योजनाएँ बनाई गई थी। परन्तु 2008 से 2013 तक की अवधि में इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण योजनाओं को गति नहीं मिल पाई तथा तत्कालीन सरकार ने 4 साल तक इन योजनाओं में बजट नहीं दिया। बाड़मेर-जैसलमेर जिले की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु **इन्दिरा गाँधी नहर पर आधारित-** (1) राजीव गाँधी लिफ्ट नहर (उम्मेदसागर-धवा-समदडी-खण्डप) राशि 585.40 करोड़ रू. (2) आर.डी. नाचना (पोखरण-फलसुण्ड-पोखरण-सिवाना) राशि 1454.20 करोड़ रू. (3) आर.डी. मोहनगढ़ (बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण)- राशि 1716.01 करोड़ रू., **नर्मदा नहर आधारित-** (4) चोहटन एवं गुडामालानी योजना- राशि 1467.08 करोड़ रू. (5) एच.आर. गुडामालानी योजना- राशि 160.00 करोड़ रू. (6) रामसागर- शिव एवं चोहटन- राशि 160.7 करोड़ रूपये **कुल-राशि 5993.00 करोड़ रू.।** यदि इन नई पाँचों योजनाओं में आगामी 3-4 साल में माँग के अनुसार पूरी राशि दी जाए तो क्षेत्र की 85 प्रतिशत जनता पाईप लाइन के माध्यम से पेयजल से लाभान्वित हो जाएगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की घोषणा और मोदी जी के सपनों को साकार करने की ओर एक अहम कदम होगा। इस संबंध में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री वसुन्धरा राजे जी ने दिनाँक 11.08.2015 को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह जी को एक डी.ओ. लेटर लिखकर 28881 करोड़ रू. की राशि की माँग की है। जिनमें से 6000 करोड़ रू. मेरे क्षेत्र से ही संबंधित है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 10.05.2015 को नियम 193 के तहत चर्चा में एवं 16.12.2015 को नियम 377 के तहत संसद की कार्यवाही में सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया था। इस संबंध में राजस्थान की जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्री जी ने भी दिनांक 04.07.2014 को केंद्र सरकार को राशि आवंटित करने हेतु आग्रह किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री जी से विशेष निवेदन करता हूँ कि जो उक्त योजनाएं बजट के अभाव में बंद हैं। उन 5 योजनाओं के लिए 6000 करोड़ रू. के बजट का इंतजाम केंद्र सरकार के एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. या अन्य सेंट्रली फंडेड स्कीम से कराये या राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक से राशि उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान कर इस क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज जारी करायें, ताकि सदियों से अभावग्रस्त जनता को राहत मिल सके।